IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY (IJARETY)

Volume 11, Issue 2, March 2024

Impact Factor: 7.394

www.ijarety.in editor.ijarety@gmail.com

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March-April 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102036

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति का बदलता स्वरुप

Anil Kumar Yadav

Assistant Professor in Political Science, Babu Shobha Ram Govt. Arts College, Alwar, Rajasthan, India

शोध सार: वर्तमान में भारत अपनी विदेश नीति में व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ-साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए सभी परिस्थितियों में अपने राष्ट्रीय हितों को साकार करने और यहां तक कि जरूरत पड़ने पर शक्ति की रणनीति का भी सहारा लेते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है।

वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत खुद को दुनिया के सामने एक ऐसे जिम्मेदार और अग्रणी शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है, जो संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने में सक्षम है और साथ साथ ही वांछित दिशा में देश की विदेश नीति के आगे ले जाने वाले अपने ऐतिहासिक परिवर्तन से भी गुरेज नहीं कर रहा है। जाहिर तौर पर यह दिशा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की दिशा में अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खुद को परिभाषित करने का प्रयास है और किसी भी सम्मानित और अग्रणी वैश्विक शक्ति की तरह उत्साह और आत्मविश्वास से भरे हुए संप्रभु राष्ट्रों में अपनी जगह बनाने की कोशिश भी है।

मूल शब्द: राष्ट्रीय हित, विदेश नीति, संरचनात्मक, वैश्विक, गुटनिरपेक्षता, संप्रभु।

I. परिचय

सही मायने में किसी देश की विदेश नीति अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों और अपनी प्राथमिकताओं को लेकर अच्छी तरह से योजनाबद्ध, सुसंगत, पूर्वनिर्धारित और नपी-तुली होती है और इस बात का भी उसमें ख्याल होता है कि उन्हें वास्तविक धरातल पर लाने के लिए वह देश किस तौर-तरीके का इस्तेमाल करता है। यह बात इस संदर्भ में है कि भारत की विदेश नीति का कोई भी आकलन या समीक्षा उन परिस्थितियों पर विचार करते समय, जिसमें यह एक विशेष दिशा में विकसित होती है, उन संरचनात्मक चुनौतियों और उनकी ऐतिहासिक रूपरेखाओं पर भी विचार करना चाहिए, जो आगे की प्रगति या अन्यथा उस देश की विदेशी नीति को प्रभावित करती हैं।

हालांकि राष्ट्रीय इतिहास और ऐतिहासिक परंपराओं, भूगोल, राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय लक्ष्यों पर सहमति, सैन्य तैयारी आदि जैसे आंतरिक कारकों के साथ-साथ वैश्विक या क्षेत्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय पदानुक्रम, वैश्विक अर्थव्यवस्था और कई अन्य जैसे बाहरी कारकों के रूप में ज्ञात कई अन्य कारक भी होते हैं और जिन्हें पूरी तरह से आंतरिक या बाहरी परिस्थितियां कहा जाता है, वे तमाम परिस्थितियां सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय या देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए गंभीरता से ध्यान देने की मांग तो करती ही हैं, इसके बावजूद उन्हें सुनियोजित रणनीति की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ उन्हें व्यवस्थित करने के लिए देश की विदेश नीति की सफलता को लेकर सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने वाला कारकों की भी आवश्यकता होती है।

इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से, भारतीय के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति, अहिंसा, गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद-विरोधी, नस्लवाद-विरोधी, रंगभेद-विरोधी, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना आदि जैसे भारत की विदेश नीति के घोषित उद्देश्यों के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए अपनी शुरुआत की।

सही अर्थों में, इन लक्ष्यों को पाने के लिए पहले से ही विश्व युद्धों के कारण दो गुटों में बंटे तत्कालीन विश्व में स्थायी शांति और अहिंसा की नींव रखने के लिए इन आदर्शों के महत्व पर जोर देने वाले स्वतंत्र भारत के निर्माता, वास्तुकार और पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू द्वारा उचित निर्णय लिया गया था।

नेहरू जी ने आजादी से पहले भी, अंतरिम परिषद के उपाध्यक्ष होने के नाते और राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए भविष्य के मामलों में स्वतंत्र भारत की भूमिका के लेकर स्पष्ट रूप से 7 सितंबर 1946 को ऑल इंडिया रेडियो पर साहसपूर्वक घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के नेतृत्व में क्रमशः दो प्रतिद्वंद्वी वैचारिक गुटों, पूंजीवाद और साम्यवाद

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March-April 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102036

द्वारा उभरे संघर्ष-उन्मुख ब्लॉक-पॉलिटिक्स प्रतिद्वंद्विता और इसी पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद शुरू हुई शीत युद्ध की शक्ति की लगातार बढ़ती राजनीति से खुद को दूर रखेगा।

जैसा कि एक प्रसिद्ध विद्वान प्रो. विमल प्रसाद कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि नेहरू जी ने यह सब अचानक रूप से अपना लिया था, इसलिए मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के उन्हीं प्राचीन नैतिक सांस्कृतिक लोकाचार और लंबे समय से स्थापित सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत के साथ ही शुरुआत की, जिसे अब तक चलाया जा रहा है और जिसे भारत के पहले के प्रधानमंत्रियों ने आगे बढ़ाया था। इन सभी बातों को भारत की एक ठोस नींव रखने की दृष्टि से ही अपनाया गया था, ताकि राष्ट्रों की वैश्विक समानता में एक मजबूत और सम्मानजनक राष्ट्र के रूप में भारत उभर सके।

वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत की संभावित विशेषताओं को फिर से स्थापित करने लिए एक नये दृष्टिकोण, गतिशीलता और इनके समावेशन पर जोर दिया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यथार्थवाद पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय नीति को एक नये, गतिशील, ऊर्जावान और उच्च आदर्श रूप में पेश किया जा सके। ये तमाम कारक अभी तक उस आदर्शवाद की अनदेखी नहीं करते रहे हैं, जो शांति, मित्रता और सहयोग और अन्य सार्वभौमिक नैतिक या नैतिक मूल्यों पर जोर देते हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दृढ़ता के साथ स्वीकार करते हैं कि अगर दुनिया में शांति रहती है, तो विकास, दोस्ती और एकजुटता, समानता, न्याय, कल्याण के साथ-साथ सभी राष्ट्रों के हितों में समग्र मानवता का विकास भी होगा। लेकिन देश की विदेश नीति के लिए हासिल की जाने वाली ये सभी संभावित उपलब्धियों, आंतरिक चुनौतियों के साथ-साथ बाहरी परिस्थितियों के सामने पेश आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों और उनकी ऐतिहासिक संरचनाओं पर निर्भर करती हैं, इसलिए इस पर विचार करने की भी आवश्यकता है ताकि भारत की विदेश नीति से जुड़ी एक यथार्थवादी दृष्टि और व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित हो, ताकि कभी भी अपने प्रयास में विफल नहीं हो सकें, क्योंकि यह तदर्थवाद पर आधारित है या केवल आदर्शवाद पर आधारित है।

जाहिर है कि यह सब शीत युद्ध के बाद के उस वैश्विक परिदृश्य की एक संक्षिप्त समीक्षा की मांग करता है, जो वास्तव में उन परिस्थितियों के कारण पेश आयी मजबूरियों के साथ-साथ भारत के समक्ष अड़चनों के पीछे के कारणों को रेखांकित करता है, जिसके कारण इसकी विदेश नीति में बड़े पैमाने पर मूलभूत परिवर्तन भी हुए हैं।

II. शीत युद्ध के बाद का परिदृश्य

वैश्विक परिदृश्य की मजबूरियां, जो कि 1990 के दशक की शुरुआत से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सामने आई, वे थीं- पूर्व सोवियत संघ के विघटन, वर्साय की संधि का खात्मा, बर्लिन की दीवार का ढहना और दोनों जर्मनी का एकीकरण, आतंकवाद और अशासकीय घटकों आदि का अचानक उदय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनेक अशांति और परेशानियों भरा काल, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका अपने पहले वाले सुपर पावर के दर्जे से आगे निकल गया था और पहली हाइपर पावर के रूप में वैश्विक केंद्र-मंच पर विराजमान हो गया और लोगों के विचारों को भी नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा, ताकि उन्हें एक विशेष दिशा में आकार देकर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल कर सके और इस तरह एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उद्भव के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में तो तत्कालीन सोवियत संघ एक प्रतिसंतुलित बल के रूप में काम करता था।

इसी तरह, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद अस्तित्व में आए कम्युनिस्ट देशों के एक स्वतंत्र ब्लॉक के रूप में सामने आए देशों और भारत से स्पष्ट रूप से अमेरिका के प्रति झुकाव की मांग की गई ताकि उन देशों के साथ-साथ भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। ऐसा नहीं था कि उस तत्कालीन सोवियत संघ ने भारत के लिए अप्रचलित और निरर्थक साबित कर देने के लिए खुद को विघटित कर दिया था, जिसने अपने सभी महत्वपूर्ण और नाजुक क्षणों में और खासकर 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय या संयुक्त राष्ट्र में भारत को अपनी सहायता और समर्थन दिया था।

इस मामले में वास्तविकता तो यही थी कि सोवियत संघ इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली नहीं रह गया था कि वह विश्व राजनीति में एक काउंटर पोल के रूप में अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देने और उसे संतुलित करने में सक्षम हो, क्योंकि यह यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंधों वाले भयंकर शीत युद्ध के वर्षों के दौरान अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। हालांकि, तत्कालीन सोवियत संघ की उस अनूठी भूमिका ने अमेरिकी हस्तक्षेप और नव-साम्राज्यवाद और अमेरिकी साम्राज्यवाद की वर्तमान नीति पर विशेष रूप से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की चल रही यूएसएसआर के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने वाली उनकी नीति के ऊपर एक निरंतर और प्रभावी अवरोध खड़ा कर दिया था।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March-April 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102036

दूसरी तरफ, यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके बीच द्वि-ध्रुवीयता और कड़वे शीत युद्ध द्वारा चिन्हित परमाणु शक्ति आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बाद शक्ति के प्रभावी संतुलन (आतंक के संतुलन) को स्थापित करने और बनाए रखने का कारण बना। गुटों में बंटी शक्ति प्रतिद्वंद्विता के इस तरह के तनावपूर्ण और भयानक वैश्विक वातावरण में पूरी दुनिया को सुपर पावर के पक्ष-विपक्ष में बांट दिया गया और इसके कारण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के महाद्वीपों में फैले गरीब, कम विकसित और विकासशील देश सबसे ज्यादा पीड़ित थे, क्योंकि वे दुनिया के इन हिस्सों में सदियों से उपनिवेशवाद के पतन के बाद अपने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्रयासों में लगे हुए थे।

वास्तव में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कथित परिचर्चा वाले परिदृश्य का संदर्भ भारत की विदेश नीति में यथार्थवाद के क्रमिक उद्भव की आवश्यकता को भी प्रस्तुत करता है और इसकी सही ढंग से चर्चा करने के साथ-साथ संरचनात्मक बाधाओं और उनकी ऐतिहासिकता की वैचारिक स्पष्टता का विश्लेषण करने की भी आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवाद और भारत की बढ़ती ताकत - वास्तव में, यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और संघर्ष संबंधी या संघर्ष आधारित पहलुओं पर जोर देने वाला कहा जाता है। वास्तव में, यथार्थवादी राज्यों को ही प्रमुख घटक मानते हैं, जो मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अपने राष्ट्रीय हितों और सत्ता के लिए संघर्ष से जुड़े होते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हित में अपनी सरकारी प्राथमिकताओं का सावधानीपूर्वक चाक-चौबंद बना रखा है, क्योंकि नेतृत्व संभालते ही विदेश नीति सम्बन्ध में उन्होंने उस संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्व और आवश्यकता को महसूस किया, जो कि भारत की अनदेखी कर रहा था।

देश की विदेश नीति के वर्तमान परिदृश्य में और तत्कालीन विश्व के सभी देशों के साथ, न केवल भारत के, बल्कि पूरे विश्व के लिए भी देश की विदेश नीति के उक्त लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से तत्कालीन सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस के साथ पारंपरिक और अमोघ मित्रता की अनदेखी भी नहीं की। इनके अलावा, उन्होंने अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इजरायल और संभावित उत्तराधिकारी रूस जैसे संभावित हथियार आपूर्तिकर्ता देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर अब तक उपेक्षा का शिकार रहा भारत की सैन्य शक्ति जैसे मुद्दों में सुधार लाया।

वास्तव में, एक उभरता हुआ भारत न केवल एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी प्राचीन संस्कृति और शास्त्रीय नैतिक और आध्यात्मिक परंपरा के साथ-साथ तथाकथित समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में अपनी विशिष्ट रहा है। पहले की भू-राजनीति में हो रहे बदलाव के इस मौजूदा दौर में, चीन और भारत जैसे पूर्व के कुछ प्रमुख सदस्य देशों के अलावा सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग आदि जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के कारण एशिया का महत्व बढ़ रहा है।

एशिया अपने कुछ सदस्य देशों, विशेष रूप से चीन और भारत द्वारा प्राप्त की गई उल्लेखनीय सफलताओं के कारण पूरी दुनिया में अपने विशाल भौगोलिक विस्तार, विशाल जनसंख्या, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, अच्छी तरह से योग्य और प्रशिक्षित मानव शक्ति, अद्भुत सैन्य शक्ति और इस तरह की अन्य विशिष्टताओं के साथ प्रभावशाली और जबरदस्त पुनरुत्थान की प्रक्रिया से गुजर रहा है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय परिदृश्य पहले से ही एक बड़े बदलाव का कारण बन गया है, जो शक्ति के वैश्विक केंद्र में बदलाव का संकेत है, क्योंकि यह शक्ति केन्द पिछले ढाई शताब्दियों से अधिक से यूरोप-अटलांटिक क्षेत्र था। इस वैश्विक बदलाव के परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रचलित विश्व राजनीति में उन पहले के अन्यायी, स्वार्थी और अनैतिक प्रवृत्तियों में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जो ज्यादातर तीसरी दुनिया के उभरते हुए राज्यों पर दबदबा रखते थे, क्योंकि ये देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इसके अलावा पूर्व सोवियत संघ की प्रमुख असमान वैश्विक शक्तियों के पीछे-पीछे चल रहे थे।

इस तरह के एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में भारत जैसा स्वतंत्र और गुटनिरपेक्ष देश और तीसरी दुनिया के कई अन्य देशों ने अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के वांछित अधिकार को सुरक्षित रख पाने में खुद को मुश्किलों में पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तरफ भारत, 1947 में स्वतंत्रता के बाद अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर विचार करने वाले राष्ट्रों के वैश्विक समुदाय में सम्मान और इज्जत के मामले में विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए हमेशा अपनी सही जगह चाहता था।

वर्तमान में भारत मानवीय प्रसायों के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को लेकर संभावित क्षमता और विकास के अलावा पूरी दुनिया में एक शांतिप्रिय, अहिंसक और आध्यात्मिक-अभौतिकीय पसंद देश के रूप में भी निरंतर विस्तार करने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी सफल होने के लिए लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है और इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता सहित विभिन्न प्रमुख बहुपक्षीय वैश्विक संस्थान में सदस्यता तथा अन्य लाभ अर्जित करने का प्रयास कर रहा है।

भारत की विदेश नीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास - यथार्थवादी दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद एक रणनीतिक संस्कृति को लेकर नई संस्कृति को विकसित करने की दिशा में एक गंभीर प्रयास है। यह रणनीतिक संस्कृति है- किसी भी तरह से

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March-April 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102036

राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए आग्रह और जोर देना, यहां तक कि एक ऐसी शक्तिशाली विदेश नीति का अनुसरण करना, जो ब्रिटेन, रूस, इजराइल, चीन जैसे सभी देश और यहां तक कि छोटी शक्तियां भी हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों का ख्याल रखती हैं, लेकिन भारत ने बार-बार संयम बरता है और स्वतंत्रता के बाद से विशेष रूप से नरम रवैये का सहारा लिया है और इससे वास्तव में भारत की छवि एक ऐसे कमजोर, अप्रतिक्रियाशील और कमजोर आत्मविश्वास वाले देश की धारणा बनी है, जो हमेशा दुनिया के अन्य सभी देशों की तरफ से पड़ने वाले सभी प्रकार के दबावों के आगे झुकने के लिए तैयार रहता है।

इसके अलावा, इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण देश की विदेश नीति के वास्तविक संचालन में भ्रम और दिशाहीनता पैदा हुई है और इसने गंभीर और सार्थक चर्चा के लिए विशेषज्ञों की संस्थाओं के गठन में भी अड़चन डाली है, जो भारतीय विदेश नीति को सुगठित करते हुए अंतिम निर्णय लेने की समझ देते हों।

इस प्रकार, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह दृष्टि अंततः मजबूत होती है, तो शायद सबसे महत्वपूर्ण तात्कालिक परिवर्तन, भारतीय राजनीति और उसके नेताओं, भारत के अभिजात्यों के साथ-साथ सेना, पुलिस और अर्द्ध-सैन्य बलों के भीतर आत्म-आश्वासन का पुनर्स्थापन होगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि इसे महत्वपूर्ण हद तक विशेष रूप से 2016 में पीओके के अंदर आतंकवादी ठिकाने के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा सफल सर्जिकल ऑपरेशन और 2017 में डोकलाम संकट के सावधानीपूर्वक निपटने के बाद पा लिया गया है, महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित भारतीय नेतृत्व के दावे के अलावा परमाणु प्रसार और पर्यावरण संबंधी चिंताओं या इस तरह की अन्य सामान्य चिंताओं और क्षेत्रीय या वैश्विक मंचों में कई चर्चाओं के दौरान नीतिगत निर्णयों के संदर्भ में उन्हें सफलतापूर्वक ले जाने जैसे मानव कल्याण से सम्बन्धित मुद्दों में भी इसे देखा गया है।

III. वैश्विक मंचो पर सशक्त भूमिका

दुनिया में सबसे बड़ा सफल और जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत के पास जानकार, कार्यशील, कुशल मजदूर, फलती-फूलती अर्थव्यवस्था और बाजार, अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास सुविधा, उन्नत उद्योगों और भारी इकाइयों से जुड़े विश्व स्तरीय बुद्धिजीवी और पेशेवर लोग हैं। शक्तिशाली सेना और मानवता के सबसे बड़े पैरोकार वैश्विक आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन आदि के संस्थापक सदस्य होने के नाते, भारत एक अच्छी तरह से उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में पहचाना जाने वाला एक देश है और इस कारण भारत का विश्वमंच पर सम्मान निरंतर बढ़ ही रहा है।

वर्ष दिसम्बर 2023 में आयोजित जी-20 सम्मेलन की भारत द्वारा अध्यक्षता करना, भारत की बढ़ती भूमिका का बहुत बड़ा प्रमाण है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ सहित सभी महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों में उपयुक्त और जिम्मेदार भूमिका के साथ भी भारत अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, ताकि यह अपने प्राचीन सांस्कृतिक लोकाचार के अनुरूप काम करते हुए, शांति, समृद्धि और सुरक्षा स्थापित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सके। पूरी दुनिया में उन देशों की संपूर्ण मानवता की समग्र प्रगति और कल्याण को सुनिश्चित करना भारत का उद्देश्य रहा है, जो लंबे समय से आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता, परमाणु युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं, भयावह महामारियों आदि के खतरों से पीड़ित और भयभीत रहे हैं।

भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। चंद्रयान-3 के साथ भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलु आत्मनिर्भरता है। भारत के आरंभिक चन्द्रयान मिशन अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर निर्भर थे। चंद्रयान-3 आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का बढ़ता कदम था।

भारत ने कोविड महामारी के दौरान इससे निपटने की प्रतिक्रिया से विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। भारत ने न केवल सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया, बल्कि विश्व का सबसे तेज टीकाकरण अभियान भी चलाया। वैक्सीन भारत में निर्मित थी। भारत ने जरूरतमंद देशों को वैक्सीन देकर उनकी मदद भी की। भारत के कोविड वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम ने 100 से अधिक देशों की सहायता की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से योग और आयुर्वेद जैसी भारत की प्राचीन परंपराओं को वैश्विक लोकप्रियता मिली है। 'नाटू नाटू' और 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' के लिए ऑस्कर जीतना हमारी सॉफ्ट पावर के लिए एक बड़ी जीत है। इसमें दुनिया भर में फैले भारतीय प्रवासी भी शामिल हैं जो सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के मूल्यों, परंपराओं और विचारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ने प्रत्येक स्तर पर देश में सकारात्मक भावना पैदा की है। आज हमारे युवा नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन रहे हैं। हर दिन नए स्टार्टअप शुरू करने में भारत नंबर-वन है। स्टार्टअप की संख्या में हम दूसरे नंबर पर हैं। सबसे बड़े स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में तीसरे नंबर पर है। आज भारत दुनिया में यूनिकॉर्न की तीसरी सबसे बड़ी संख्या वाला देश है। 2021 में, हमने हर 29 दिन में एक यूनिकॉर्न जोड़ा और 2022 में, हमने हर 9 दिनों में एक यूनिकॉर्न जोड़ा।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March-April 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102036

भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन पहल और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। हम उन 26 देशों में से हैं जिन्होंने प्रारंभिक अनुकूलन संचार के साथ 2019 की ग्रीनहाउस गैस सूची के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के साथ अपना विचार-विमर्श साझा किया है। भारत ने जलवायु कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, लीड-आईटी, सीडीआरआई, आईआरआईएस, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस जैसे मंचों की शुरुआत की है। भारत ने 2030 के लिए निर्धारित नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को 2020-21 में हासिल कर लिया।

इसके अलावा वर्तमान में चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध में विश्व के कई देशों के द्वारा भारत से इस दोनों देशों के मध्य बढ़ते तनाव को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने की अपील की है जो वर्तमान में भारत की बढ़ती शक्ति का परिचायक है।

IV. विदेश नीति में बदलाव

हालाँकि वैश्विक शक्ति प्रणाली को विश्व में भारत के प्रभाव के बढ़ते दबदबे पर विचार करना चाहिए, लेकिन भारत को भी इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अपने दावे की योग्यता साबित करने के लिए आगे आना चाहिए जैसा कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश मुक्ति के दौरान 1971 के भारत-पाक युद्ध में साबित की थीं। दुनिया को तभी पता चल पाया कि गुटनिरपेक्षता की भारत की नीति केवल दूसरों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगने नहीं रही है, बल्कि यह सभी बाधाओं और उभरती हुए शत्रुतापूर्ण बड़ी और प्रमुख शक्तियों के बीच के गठबंधन यानी अमेरिका-चीन-पाक के धुरी जैसी तत्कालीन चुनौतियों के खिलाफ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उनके संरक्षण के लिए खुद के द्वारा सार्थक कार्यों को आगे बढ़ाने वाले साहस के साथ खड़ा है।

तब से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के प्रायोजित सीमा पार से होने वाले आतंक से दशकों से गंभीर रूप से पीड़ित होने और बिना किसी साहस और मुखर जवाबी कार्रवाई के भारत के क्षेत्र में चीन के लगातार घुसपैठ से पीड़ित होने के बावजूद भारत अपने गौरवशाली अतीत में नहीं लौट सका। इस प्रकार, इंदिरा गांधी के बाद से देश की असंगत विदेश नीति और कूटनीति के कारण भारत को बुरी स्थिति में डालने वाले असमानतापूर्ण दृष्टिकोण और इसके कारण नरम शक्ति की छवि पैदा हुई, जो अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए खुद को खड़ा करने में असमर्थ है।

अमेरिकी नेतृत्व में चले पश्चिमी देशों के एजेंडे ने अंततः 1990 में शीत युद्ध के पतन के साथ गुटनिरपेक्षता की अंतर्निहित शक्ति को समाप्त कर डाला और उन्हें भारत के बढ़ते प्रभाव को वश में करने के लिए चीन और पाकिस्तान को एक अवसर प्रदान किया। वह प्रयास वास्तव में एक शातिर जाल था, जो अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी शक्तियों द्वारा भारत को इस तरह से फंसाने के लिए फैलाया गया था, ताकि भारत अपने स्वयं के वास्तविक अधिकारों और दावों और कथित राष्ट्रीय हितों के लिए स्वयं का दावा करने में सक्षम न हो पाये, क्योंकि गुटनिरपेक्षता और इस तरह से बनायी गई विदेश नीति के अपने स्व-सिद्ध सिद्धांत इसकी वास्तविक ताकत थी, जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय नैतिक मूल्यों में निहित थी और दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी तरह की चुनौती से परे थी। इन अमेरिकी अहंकार और भारतीय विरोधी रुख के बावजूद, क्रूर शक्ति आधारित पदानुक्रमित और शातिर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और भारत की आर्थिक और तकनीकी बाधाओं और इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि को संरक्षित करने की मजबूरियों और चीनी-पाक की मिलीभगत के कारण बढ़ते खतरे और वैश्विक आतंकवाद और देश के खिलाफ चल रहे धार्मिक कट्टरवाद सहित आईएसआईएस के आतंकी खतरे के बढ़ते खतरे के कारण को देखते हुए भी भारत के पास अमेरिका से समर्थन और सहयोग लेने के अलावा कोई चारा नहीं है।

लेकिन वर्तमान में भारत की सांस्कृतिक ताकत अभी भी अमेरिका को पीछे छोड़ रही है, भारत अपनी अद्वितीय नैतिक-सांस्कृतिक शक्ति के माध्यम से पूरी दुनिया की निगरानी कर सकता है। यही कारण है कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भारत के साथ चल रहे सैन्य सहयोग को तुरंत रोकने के लिए कहा था। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी भारत को विश्व के सबसे बढ़ते प्रभावशाली देशों में शामिल किया है।

V. आवश्यकता

जैसा कि स्पष्ट है कि कुछ समय के लिए अमेरिका के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाए रखना भारत की आवश्यकता है, भले ही यह एक पक्षीय हो, क्योंकि यह प्रभावी रूप से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए नहीं रख सकता है और चार अन्य स्थायी सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ-साथ और जी-2 मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह आदि जैसे अन्य प्रमुख समूहों के साथ-साथ अमेरिका का अपने पक्ष में सहमति लिये बिना सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनने के अपने लंबे पोषित सपने को पूरा नहीं कर सकता है।

भारत को न केवल आधुनिक तकनीक, उन्नत सैन्य हथियारों और अन्य आर्थिक लाभ के लिए, बल्कि इस्लामिक स्टेट, जैश-ए मुहम्मद, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एच-उल-एम), हक्कानी आतंकी नेटवर्क, हाफिज सईद के आतंकी संगठन जैसे वैश्विक पहुंच वाले

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March-April 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102036

कई आतंकी संगठनों और भारत में सीमा पार से होने वाले आतंक के निर्यात को रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव के लिए भी अमेरिकी समर्थन की जरूरत है।

वास्तव में, भारत आतंकवाद से सबसे बुरी तरह पीड़ितों में से एक है, जिसने पहले ही अपने दो बहुत ही होनहार प्रधानमंत्री, स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी को खो दिया है, इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में 26ध्11, बंग्लोर बेकरी हमला, दिल्ली उच्च न्यायालय, भारतीय संसद आदि पर कई खतरनाक आतंकवादी हमलों और विशेष रूप से पीओके में भारत की सफल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद नियमित रूप से जम्मू-कश्मीर में स्कूलों को जलाने, हर दिन एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन, कई बहादुर सैनिकों और निर्दोष कश्मीरी नागरिकों की हत्या जैसे आतंकी हमलों का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रभावी संरचना - इसलिए, भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ सीमा पार से होने वाले आतंक और अन्य वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक ऐसी मजबूत और प्रभावी सुरक्षा संरचना की आवश्यकता है, जो आतंकवादियों की आवाजाही और उनके भविष्य के लक्ष्य को लेकर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उनकी निगरानी करे और सूचना साझा करे ताकि देश में किसी भी संभावित आतंकी हमले को रोका जा सके।

इसके अलावा सभी आतंकवादियों, आतंकी नेटवर्क और उनके प्रायोजक राष्ट्रों को अलग-थलग करने की कूटनीतिक कोशिशों के साथ-साथ आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का ईमानदारी से अनुसरण किया जा सके। इस प्रयास में, अमेरिका और रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और इजरायल जैसे कुछ उन्नत पश्चिमी देशों का समर्थन निश्चित रूप से बहुत ही मायने रखता है। इस लिहाज से भारत पहले से ही अमेरिका द्वारा प्रायोजित किकलेटर समझौते में पहले से ही शामिल है, जिसके कारण अमेरिका के प्रति बढ़ती झुकाव को लेकर भारत की कठोर आलोचना हुई।

इसके बाद, भारत ने 2008 में अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौते को अंजाम दिया, जिसने विक्रेताओं की देयता के मुद्दे को लेकर कुछ बाधाओं के बावजूद अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी का एक नये युग की शुरुआत की। उस समय के उभरे परिदृश्य में भारत ने अपने सबसे भरोसेमंद मित्र, रूस को भी नजरअंदाज कर दिया, जिस कारण दक्षिण एशिया और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखने के लिए रूस को पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए मजबूर कर दिया।

हालांकि भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के तहत आर्थिक, सुरक्षा, तकनीकी और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों में अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए उत्साह से काम किया, और अमेरिकी प्राथमिकताओं और चिंताओं को समायोजित करने और अपने नए स्थापित सम्बन्धों को मजबूत करने को लेकर अपने लंबे समय के आदर्श और लक्ष्यों के साथ भी महत्वपूर्ण समझौता भी किया, लेकिन अमेरिका ने हमेशा एक ओर पाकिस्तान के साथ और दूसरी ओर चीन के संतुलन बनाते हुए भारत की चिंताओं के साथ दोहरा खेल खेला और अब तक कभी भी स्थायी सदस्यता और पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और एशिया-प्रशांत विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक-सैन्यवादी दावे के साथ-साथ भारत और हिंद महासागर क्षेत्र और पूरे हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के अन्य तटीय देशों के हित को लेकर भारत की चिंता का समर्थन कभी नहीं किया।

इसलिए, भारत के पास अपनी वांछित राष्ट्रीय हितों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए शक्ति की व्यावहारिकता के प्रति अपनी मौजूदा अमेरिकी विदेश नीति को संशोधित करने के अलावा कोई चारा नहीं है। यही कारण है कि भारत ने एक बार फिर से राष्ट्रपति पुतिन से मित्रता करने के लिए रूस की ओर रुख किया है और अपने पारस्परिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को फिर से मजबूत करने का संकल्प लिया है।

यह वास्तव में भारत के रूस के साथ उपेक्षित और शिथिल पड़ रहे सम्बन्धों में ताजगी लायेगा। पीओके में भारत की उस सफल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आयी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, जिसने पाकिस्तान के मनोबल को तोड़कर रख दिया है और साथ ही जिसने आतंकवादियों को अपने ठिकाने में कैद रहने पर मजबूर कर दिया है, इससे इस्लामाबाद बौखलाया हुआ है और भारत को अलग-थलग करने के लिए बड़े पैमाने पर जवाबी कोशिश कर रहा है और इस प्रयास में पाकिस्तान को चीन का पूर्ण समर्थन भारत के लिए अत्यधिक चिंता का विषय बना हुआ है।

इसके अलावा, चीन की भारत विरोधी उस शातिराना और ईर्ष्यापूर्ण भूमिका को भी नहीं भूलना चाहिए, जो गोवा में आयोजित पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में स्पष्ट हो गया था, जिसमें चीन ने आतंकवाद के खात्मे को लेकर भारत के उस ईमानदार प्रयासों में भी रोड़ा अटका दिया था, जिसमें सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद भी शामिल था, जिसमें चीन ने कहा था कि किसी भी देश का नाम आतंकवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और यह भी कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के महान उद्देश्यों को लेकर इस्लामाबाद द्वारा दिए गए महान बलिदानों को नहीं भूलाया जाना चाहिए।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March-April 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102036

इसके अलावा, चीन ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा मौलाना मसूद अजहर को आतंकवादी के रूप में नामित करने के भारत के प्रयास में भी बाधा डाल दिया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को लेकर भी उसने अपना दोहरापन दिखाया।

वास्तव में, चीन-पाकिस्तानी के बीच इस तरह के बढ़ते सम्बन्ध के इशारे न सिर्फ भारत और दक्षिण एशिया की शांति और सुरक्षा के लिए, बल्कि पूरे हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बुरा संकेत हैं, जिसमें चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपने समुद्री क्षेत्र में संलग्न करने के दृष्टिकोण के साथ बहुत दिलचस्पी रखता है, हालांकि, हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। इस कानूनी हार ने चीन को बहुत आक्रामक बना दिया है और उसने भारत को घेरने की दृष्टि से पाकिस्तान की मदद करते हुए अन्य कुटिल रणनीति अपनाना शुरू कर दिया है। जाहिर है कि भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चे पर दुश्मन देशों की मौजूदगी है। इसलिए इसे अपनी विदेश नीति को यथार्थवाद के प्रति अनुकूल बनाना होगा ताकि भारत एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सके।

VI. निष्कर्ष

वर्तमान दौर में भारत की विदेश नीति निश्चित रूप से अपने एक नए मुकाम को प्राप्त कर रही है। भारत ने अपनी विदेश नीति में आदर्शवाद और यथार्थवाद का सुखद संतुलन बनाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है और इस रूप में भारत अपने विदेश नीति को नए रूप में डालकर अपने संबंधों को पुनः निर्धारित कर रहा है।

भारत की विदेश नीति को पुनर्जीवित और मजबूत बनाने वाली राजनीतिक-प्रशासनिक कवायद, अपने देश को दुनिया में एक अग्रणी शक्ति बनने के लिए देश की बढ़ती ताकत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने देश में आये नया इस आत्मविश्वास को प्रकट करती है कि कैसे शीर्ष भारतीय राजनीतिक नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व मामलों में अपनी भूमिका की कल्पना करता है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया है कि सभी तरह की कठिनाइयों और बाधाओं को उन दृढ़ प्रतिबद्धता और ईमानदार प्रयासों से दूर किया जा सकता है, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए दर्शा रहे हैं। इससे तो एक कहावत जरूर चरितार्थ होती है कि 'मानव प्रयास से परे कुछ भी नहीं है।'

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1) मेहरोत्रा, एस. आर., टुवर्ड्स इंडियाज फ्रीडम एण्ड पार्टिशन, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा. लि., नई दिल्ली, 1976, पृ. 46-48.
2) श्रीवास्तव, एम. पी., कॉन्स्टिट्यूशनल एण्ड नेशनल डवलमेंट इन इण्डिया, एस. एस. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1981, पृ. 31.
3) प्रसाद, ज्योति, इण्डियन कॉन्स्टिट्यूशनल डवलपमेन्ट, के. नाथ एण्ड कं., मेरठ, 1970, पृ. 17-20.
4) गुप्ता, शिशिर, कश्मीर स्टडी इन इण्डिया-पाकिस्तान रिलेशन्स, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, न्यूयार्क, 1996, पृ. 18.
5) सिंहल, दामोदर पी.,नेशनलिज्म इन इण्डिया एण्ड अदर हिस्टोरिकल एसेसेज, मुंशी राममनोहर लाल ओरियन्टल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1997, पृ. 98.
6) मिश्रा, पुष्पेंद्र कुमार, भारत-पाक संबंध : एक पूनर्वेक्षण, क्लासिकल पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2016, पृ. 46.
7) पाटिल, पी. टी., नेहरू एण्ड दी फ्रीडम मूवमेन्ट, स्टेलिंग पब्लिशर्स, न्यू देहली, 1960, पृ. 24.
8) जेफफरीज, सी., दी ट्रांसफर ऑफ दी पावर, मैकमिलन, लन्दन, 1960, पृ. 116.
9) मजूमदार, आर. सी., हिस्ट्री ऑफ दी फ्रीडम मूवमेन्ट, साइंटिफिक बुक एजेन्सी, कलकत्ता, 1962, पृ. 142-145.
10) 10. शास्त्री, प्रकाशवीर, कश्मीर और भारत पाक संबंध, अमर सत्य प्रकाशन, 2019, पृ. 32.
11) ब्रिगेडियर, सिन्हा, दीपक, बियोन्ड द बेओट, ज्ञान पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2006, पृ. 64.
12) सभरवाल, शरत, भारत की पाकिस्तान पहेलीः एक जटिल संबंध का प्रबंधन, रूटलेज प्रकाशन, नई दिल्ली, 2022, पृ. 22.
13) शर्मा, जे. एस., इण्डियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, न्यू देहली, 1962, पृ. 7.
14) मेनन, वी. के., दी स्टोरी ऑफ दी इन्टेग्रेशन ऑफ दी इण्डियन स्टेट्स, मेकमिलन, न्यूयॉर्क, 1956, पृ. 77.
15) गुप्ता डी. सी., इन्टरनेशनल अफेअर्स पार्ट-2, 1946-61, मेट्रोपोलिटन बुक वर्क्स, दिल्ली, 1962, पृ. 88.
16) दीक्षित, संजय, अनब्रेकिंग इंडिया डिसीजन ऑन आर्टिकल 370 एंड सीएए, गरुड़ प्रकाशन, 2020, पृ. 53.
17) ब्रिगेडियर, लाल, ए.के., नीयो-टैरेरिज्म, ज्ञान पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2004, पृ. 6.
18) गुप्ता, कुरुनाकर, इण्डिया इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ए पीरिअड ऑफ ट्रांजिशन, सांइटिफिक बुक एजेन्सी, कलकत्ता, 1966, पृ. 203-204.
19) यादव, हिमांशु, भारत-पाक संबंध : आतंक से सर्जिकल स्ट्राइक तक, राज पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2018, पृ. 38.

समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ -

20) हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March-April 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102036

21) द हिन्दू नई दिल्ली
22) दनिक भास्कर राजस्थान
23) जनसत्ता नई दिल्ली
24) इण्डियन एक्सप्रेस
25) योजना
26) कुरुक्षेत्र
27) इण्डिया टुडे
28) आउटलुक
29) प्रतियोगिता दर्पण

IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and Technology

ISSN: 2394-2975 Impact Factor: 7.394

www.ijarety.in editor.ijarety@gmail.com